नागरिक विविध

जी. डी. खोसला, सी.जे., और ए. एन. ग्रोवर, जे. के समक्ष।

आयकर आयुक्त,-याचिकाकर्ता।

बनाम

मेसर्स भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, - प्रतिवादी।'

1957 का आयकर सिविल संदर्भ संख्या 6 डी

भारतीय आयकर अधिनियम (1922 का XI) - अनुसूची के नियम 3 (बी) का प्रावधान - प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को सही करने के लिए आयकर अधिकारी की शक्ति का अर्थ और दायरा - नियंत्रक के परामर्श की सीमा बीमा का - जब आवश्यक हो, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की अनुसूची के नियम 3(बी) के प्रावधान का अर्थ है कि यदि प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास होता है, तो ऐसा मूल्यह्रास एक अनुमेय कटौती बन जाता है और यदि कोई मूल्यह्रास होता है , परिणामी वृद्धि को उस अधिशेष में जोड़ा जाना चाहिए जिससे कर योग्य राशि की गणना की जानी है। हालाँकि, ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियों के एक समूह के कारण आरक्षित निधि में राशि और देनदारी, जिसे पूरा करने का इरादा है, में काफी असमानता दिखाई दे। बकाया पॉलिसियों के संबंध में आरक्षित निधि देनदारी से बहुत अधिक हो सकती है या यह उससे काफी कम हो सकती है। इन दोनों मामलों में आयकर अधिकारी को बीमा नियंत्रक से परामर्श करने के बाद आवश्यक समायोजन करने की अनुमति है।

माना गया कि नियम 3(बी) का प्रावधान ऐसे मामले पर लागू नहीं होता है जहां आयकर अधिकारी को यह देखना होता है कि प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। उसे बीमा नियंत्रक के संदर्भ के बिना खुद को संतुष्ट करना होगा कि जिन प्रतिभूतियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जा रहा है, वे मूल्यह्रास या हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं हैं जो वास्तव में हुआ है या वास्तव में भुगतना पड़ा है, और इसे निर्धारित करने के लिए उसे अवश्य करना चाहिए प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन हो। प्रावधान का इरादा यह है कि जहां गणना की शुद्धता से संबंधित एक कठिन और जटिल मामला है, आयकर अधिकारी को अपने ज्ञान के आधार पर कोई भी बदलाव करने से पहले बीमा नियंत्रक की सलाह लेनी चाहिए। हालाँकि, आयकर अधिकारी को गलत या धोखाधड़ी वाले मूल्यांकन को सही करने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है और

प्रावधान का उद्देश्य उन मामलों को कवर करना नहीं है जहां एक करदाता, आयकर से बचने के लिए, अपनी प्रतिभूतियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करते समय अधिक मूल्य देता है या

आरक्षित निधि की मात्रा में मूल्यह्रास दिखाने के लिए उन प्रतिभूतियों का कम मूल्यांकन करता है जो पहले से ही आरक्षित निधि में हैं। बीमा नियंत्रक से केवल उन मामलों में परामर्श किया जाना चाहिए जहां प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को सही मानते हुए आयकर अधिकारी को इनके बीच असंगतता मिलती है।

आरक्षित निधि की राशि और बकाया पॉलिसियों के संबंध में देयता की राशि। आयकर अधिकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को सही करने से पहले बीमा नियंत्रक से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसे करने का उसका पूरा अधिकार क्षेत्र है।

भारतीय आय की धारा 66(1) के तहत संदर्भ कर अधिनियम, 1922 (19^2 का XI) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मामले को बताने और इसे कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर संदर्भित करने के लिए: -

"क्या ट्रिब्यूनल द्वारा पाए गए तथ्यों पर, आयकर अधिकारी के पास इस मामले में भारतीय आयकर अधिनियम की अनुसूची के नियम 3 (बी) के संदर्भ में समायोजन करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था?"

श्री हरदयाल हार्डली एवं श्री. डी.के. कपूर, एडीवीओ-ए याचिकाकर्ता की ओर से कहते हैं।

श्री टी. पी. एस. चावला, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

डी. खोसला, सी. जे.,-1957 के नागरिक संदर्भ संख्या 6-डी/ में भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के तहत हमारी राय के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कानून के निम्नलिखित प्रश्न को हमारे पास भेजा गया है:

"क्या ट्रिब्यूनल द्वारा पाए गए तथ्यों पर, आयकर अधिकारी के पास इस मामले में भारतीय आयकर अधिनियम की अनुसूची के नियम 3 (बी) के संदर्भ में समायोजन करने का अधिकार क्षेत्र था ?"

मूल रूप से आयकर आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में था:

"क्या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की अनुसूची , नियम 3 (बी) का प्रावधान लागू था और क्या आयकर अधिकारी इस मामले में बीमा नियंत्रक से परामर्श करने के लिए बाध्य था, जहां ब्याज दर के बारे में कोई सवाल नहीं उठता था या बकाया पॉलिसियों के संबंध में दायित्व निर्धारित करने में नियोजित अन्य कारक?"

ट्रिब्यूनल ने यह विचार किया कि जिस प्रश्न को दोबारा तैयार किया गया था और वास्तव में हमारी राय के लिए संदर्भित किया गया था वह इस मामले में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक था और इसलिए, आयकर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित वाक्यांशविज्ञान को अपनाना अनावश्यक था। आयकर आयुक्त ने हमारे पास एक नया आवेदन किया है (आयकर मामला संख्या 6-डी/1957) जिसमें प्रार्थना है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाए कि वह प्रश्न को मूल रूप से उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न के रूप में संदर्भित करे। वास्तव में संदर्भित प्रश्न का। वर्तमान में यह देखा जाएगा कि दोनों प्रश्नों के सार में कोई अंतर नहीं है और हमारे सामने छूटे हुए बिंदुओं को वास्तव में संदर्भित प्रश्न पर विचार करके निपटाया जा सकता है।

जिन परिस्थितियों में मामला उठा, वे इस प्रकार हैं: निर्धारिती भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो बीमा व्यवसाय करती है। मूल्यांकन के वर्ष 1952-53, 1953-54 और 1954-55 हैं। आयकर कार्यालय को भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(7) द्वारा निर्देशित अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार इस कंपनी के लाभ का आकलन करना था। धारा 10(7) निम्नलिखित शर्तों में है:

" धारा 8 , 9 , 10 , 12 या 18 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद , बीमा के किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ और उस पर देय कर की गणना इस अधिनियम की अनुसूची में निहित नियमों के अनुसार की जाएगी।"

अनुसूची जीवन बीमा व्यवसाय के कर योग्य लाभ और लाभ की गणना के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया बताती है। आयकर अधिकारी ने मुनाफे की गणना में रुपये की राशि को अस्वीकार कर दिया। कुल राशि 1,75,000 रु. 18,75,000 जो कंपनी द्वारा ट्रांसफर (एसआईसी) रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिए गए थे। यह राशि (1,75,000 रुपये) उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिसके द्वारा बीमा कंपनी द्वारा रखी गई कुछ प्रतिभूतियों का कम मूल्यांकन किया गया था और रुपये की राशि। 30,420 31-12-1951 को निवेश आरक्षित निधि के क्रेडिट में वास्तविक शेष का प्रतिनिधित्व करता है जो गणना करने के लिए प्रासंगिक तारीख है। बीमा कंपनी ने वहां प्रतिभूतियों का मूल्य रु. 18,75,000 और आयकर अधिकारी की राय में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कम किया गया था।

इस मामले में विवाद की प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बीमा कंपनी के लाभ और लाभ की गणना के तरीके को संक्षेप में बताया जाए। बीमा कंपनी की आय में प्राप्त

प्रीमियम और उसके निवेश पर ब्याज शामिल होता है। देनदारियों में प्रबंधन व्यय और पॉलिसी धारकों को परिपक्व होने वाली पॉलिसियों के कारण भुगतान की गई राशि शामिल होती है। अनुसूची में लाभ की गणना के लिए दो तरीके बताए गए हैं। अनुसूची के नियम 2(ए) के तहत प्रबंधन व्यय को आने वाले सकल बाह्य से घटा दिया जाता है और परिणामी आंकड़ा लाभ और लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

दूसरी विधि थोड़ी अधिक जटिल है और अधिशेष के वार्षिक औसत पर आधारित है जो नियम 2(बी) के तहत निर्धारित तरीके से निकाला जाता है। दोनों तरीकों से प्राप्त दो आंकड़ों में से जो आंकड़ा बड़ा है, उसे कर योग्य लाभ माना जाएगा। वर्तमान मामले में आयकर अधिकारी द्वारा दोनों तरीकों को अपनाया गया था, और चूंकि पहली विधि ने घाटा दिया था, इसलिए उसने दूसरी विधि द्वारा दिए गए आंकड़े को अपनाया। बीमा व्यवसाय की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए विधानमंडल ने पुलिस-धारकों के हितों की कुछ सुरक्षा प्रदान की है। इनमें से एक आरक्षित निधि बनाए रखने की बाध्यता है। प्रतिभूतियों और नकदी के रूप में संपत्ति समय-समय पर इस निधि में स्थानांतरित की जाती है।

इस फंड की मात्रा बकाया पॉलिसियों के संबंध में कंपनी की देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। चूंकि प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार की कीमतों में भिन्नता के साथ बदलता रहता है, इस आरक्षित निधि की मात्रा बढ़ या घट सकती है। यदि बकाया पॉलिसियों के संबंध में देनदारियों को पूरा करने के लिए मूल्य आवश्यक राशि से कम हो जाता है, तो इसे आगे के हस्तांतरण द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि प्रतिभूतियों की कीमत बढ़ती है या किसी अन्य कारण से राशि वास्तविक देनदारियों से अधिक हो जाती है, तो संबंधित समायोजन करना होगा। अपेक्षित आंकड़े पर इसे बनाए रखने के लिए आरक्षित निधि में वास्तविक और वैध तरीके से हस्तांतरित की जाने वाली राशि, आयकर के प्रयोजनों के लिए कुल लाभ से अनुमेय कटौती है।

यदि बड़ी रकम स्थानांतरित की जाती है, तो कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। आयकर अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में जो हुआ वह यह था कि रुपये की रकम. 18,75,000 को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। निर्धारिती ने प्रतिभूतियों को स्थानांतरित कर दिया, जिसका मूल्य उसने रुपये के आंकड़े पर दिखाया। 18,75,000. वास्तव में, इन प्रतिभूतियों का मूल्य काफी अधिक था और इसलिए, अतिरिक्त को स्वीकार्य कटौती के रूप में नहीं माना जा सकता था। साथ ही रु. 30,420 रुपये की बड़ी रकम का हिस्सा था. 22,64,733 जो निर्धारिती कंपनी द्वारा निकाले गए मूल्यह्रास का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में, वास्तविक मूल्यह्रास रुपये से कम था। 30, 420. इसलिए, इस राशि को अनुमेय कटौती के रूप में नहीं माना जा सकता है।

आयकर कार्यालय ने तदनुसार रुपये की राशि को अस्वीकार कर दिया। निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतियों से 1,75,000 रु. निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त से अपील की और इस प्राधिकरण ने राशि घटाकर रु। 1,45,000. निर्धारिती ने अपीलीय न्यायाधिकरण में एक और अपील की और उसी समय आयकर अधिकारी ने रुपये की कटौती के खिलाफ अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा 30,000 रु. ट्रिब्यूनल ने माना कि चूंकि आयकर अधिकारी ने इस मद को अस्वीकार करने से पहले बीमा नियंत्रक से परामर्श नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया था। तदनुसार निर्धारिती की अपील को पूरी तरह से अनुमति दी गई और आयकर कार्यालय की अपील खारिज कर दी गई। इस पर आयकर आयुक्त ने कानून के उपर्युक्त प्रश्न को इस न्यायालय में संदर्भित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 66 के तहत एक आवेदन किया।

प्रश्न से निपटने से पहले आयकर अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों का कम मूल्य निर्धारण करने के लिए दिए गए कारणों को संक्षेप में बताना आवश्यक है। आयकर अधिकारी जिस पहली वस्तु से निपटते थे वह सरकारी प्रतिभूतियाँ थीं। सर्वप्रथम 1946-86 में 3 प्रतिशत ऋण था। कलकत्ता एक्सचेंज के आधिकारिक उद्धरण के अनुसार बाजार दर रुपये थी। 100 जबकि निर्धारिती ने बॉम्बे दर रुपये ली थी। 99-15-0. इसी प्रकार, 1955 के 2 1/2 प्रतिशत ऋण के कैड में आधिकारिक कलकत्ता एक्सचेंज कोटेशन रु. था। 98-5-0 और निर्धारिती द्वारा उल्लिखित दर रु. 98.

अंत में, 1957 का ऋण रुपये पर दिखाया गया था। 97-13-0 जबकि कलकत्ता आधिकारिक कोटेशन रु. 98. आयकर अधिकारी का विचार था कि कलकत्ता एक्सचेंज द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों को अपनाया जाना चाहिए, और इस आधार पर उन्होंने पाया कि रुपये की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों का कम मूल्यांकन किया गया था। 27,416. हालांकि अपीलीय सहायक आयुक्त ने कहा कि अंतर बहुत छोटा था और निर्धारिती के आंकड़ों को स्वीकार किया जाना चाहिए था। आयकर अधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस धारणा पर काम किया कि ये प्रतिभूतियाँ बेची नहीं गई थीं और ऐसा कोई कारण नहीं था कि कलकत्ता एक्सचेंज का आधिकारिक उद्धरण इन प्रतिभूतियों के मूल्य की गणना का आधार न बने।

दूसरा आइटम वरीयता शेयर था। निर्धारिती द्वारा भारत फायर और जनरल शेयरों का मूल्य रु. 60, लेकिन आयकर अधिकारी ने उनका मूल्य रु. 65. यह आंकड़ा आयकर अधिकारी द्वारा उस पत्र के आधार पर अपनाया गया था जो निर्धारिती द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया था और इस पत्र के अनुसार भारत फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों का वास्तविक हस्तांतरण रुपये पर किया गया था। 65. अन्य वरीयता शेयर डालमिया दादरी सीमेंट के थे। निर्धारिती द्वारा इनका मूल्य रु. 60, जबकि आयकर अधिकारी ने संबंधित अवधि के दौरान कुछ लेनदेन के आधार पर यह आंकड़ा रु. 70.

उन्होंने अपने आदेश में देखा कि डालमिया दादरी सीमेंट के शेयरों ने आयकर से मुक्त 6 प्रतिशत का लाभांश दिया था और 6 प्रतिशत कम का लाभांश देने वाली एक अन्य डालमिया कंपनी का मूल्यांकन लागत मूल्य पर निर्धारिती द्वारा किया गया था, और डालमिया के बाद से दादरी सीमेंट ने जितना बेहतर रिटर्न दिया, उनके शेयरों की कीमत डालमिया जैन एविएशन के शेयरों की कीमत से अधिक होनी चाहिए। अंतिम आइटम साधारण शेयर था। निर्धारिती द्वारा बैंक ऑफ बिहार के पूर्ण प्रदत्त शेयरों का मूल्य रु. 150 और इस आंकड़े को आयकर अधिकारी ने स्वीकार कर लिया।

आंशिक रूप से भुगतान किए गए बैंक ऑफ बिहार शेयरों का मूल्यांकन निर्धारिती द्वारा रु। 60 और आयकर अधिकारी ने हालांकि कहा कि यह एक बड़ा कम विवरण था, क्योंकि प्रत्येक शेयर पर रु. 100, रु. 50 प्रीमियम का भुगतान किया गया था और इसलिए, शेयरों का भुगतान केवल रुपये की सीमा तक किया गया था। 50 प्रतिशत, रुपये की राशि. इन शेयरों को प्राप्त करने पर वास्तव में 100 रुपये खर्च किए गए थे (शेयरों का आंशिक मूल्य 50 रुपये और प्रीमियम 50 रुपये)। इस परिस्थिति को देखते हुए आयकर कार्यालय ने शेयरों का मूल्य रु. 100. इन वस्तुओं में उन्होंने रुपये की राशि जोड़ी। 30,420 का उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार कुल मिलाकर रु. 1,89,185 जो अनुमेय कटौती में अधिकता को दर्शाता है। हालाँकि, उन्होंने केवल रुपये की राशि को अस्वीकार कर दिया। 1,75,000.

इसलिए, यह देखा जाएगा कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में आयकर अधिकारी ने जो कुछ किया वह प्रतिभूतियों का मूल्य उस पर करना था जिसे वह उचित मूल्य मानता था। उनकी राय में वास्तव में आवश्यकता से अधिक और किताबों में दिखाए गए से अधिक राशि आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों का कम मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, राशि को कम करने और कर योग्य आय में कटौती को शामिल करना उचित था।

हालाँकि, निर्धारिती का मामला यह है कि यह पुनर्मूल्यांकन और परिणामी कटौती नियंत्रक से परामर्श के बिना नहीं की जा सकती थी जैसा कि नियम 3 (बी) के प्रावधान में प्रदान किया गया है। नियम 3(बी) की शब्दावली और उसके परंतुक की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है, जिसमें लिखा है-

"3 (बी) प्रतिभूतियों या अन्य परिसंपत्तियों की वसूली पर मूल्यह्रास या हानि को पूरा करने के लिए खातों में या बीमांकिक मूल्यांकन बैलेंस शीट के माध्यम से लिखी गई या आरक्षित किसी भी राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, और किसी भी राशि को क्रेडिट में लिया जाएगा प्रतिभूतियों या अन्य परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर मूल्य वृद्धि या लाभ के कारण खातों या बीमांकिक मूल्यांकन बैलेंस शीट को अधिशेष में शामिल किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि बीमा नियंत्रक के साथ परामर्श के बाद जांच करने पर आयकर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि भाग लेने वाले पॉलिसी धारकों को बोनस और आकस्मिकताओं के लिए उचित प्रावधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ब्याज की दर या नियोजित अन्य कारक बकाया पॉलिसियों के संबंध में दायित्व निर्धारित करने में प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के साथ भौतिक रूप से असंगत है ताकि कृत्रिम रूप से अधिशेष को कम किया जा सके, इस तरह के समायोजन को मूल्यह्रास के लिए भत्ते या इसमें शामिल की जाने वाली राशि के लिए किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों की सराहना के संबंध में अधिशेष, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिशेष को एक ऐसे आंकड़े तक बढ़ा देगा जो उचित और उचित है;"

हम यहां मूल्यह्रास और प्रशंसा दोनों के मामले से निपट रहे हैं। मूल्यह्रास रुपये की राशि का है. 30,420 और यह प्रशंसा उन प्रतिभूतियों के संबंध में बताई गई है जिनका विवरण ऊपर दिया गया है। उपरोक्त प्रावधान का मतलब यह है. यदि प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास होता है, तो ऐसा मूल्यह्रास एक अनुमेय कटौती बन जाता है। यदि कोई सराहना होती है, तो परिणामी वृद्धि को उस अधिशेष में जोड़ा जाना चाहिए जिससे कर योग्य राशि की गणना की जानी है। हालाँकि, ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियों के एक समूह के कारण आरक्षित निधि में राशि और देनदारी, जिसे पूरा करने का इरादा है, में काफी असमानता दिखाई दे।

बकाया पॉलिसियों के संबंध में आरक्षित निधि देनदारी से बहुत अधिक हो सकती है या यह उससे काफी कम हो सकती है। इन दोनों मामलों में आयकर अधिकारी को बीमा नियंत्रक से परामर्श करने के बाद आवश्यक समायोजन करने की अनुमति है। समायोजन "भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों को बोनस और आकस्मिकताओं के लिए उचित प्रावधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए" भुगतान करने के बाद किया जाना चाहिए। असमानता का अस्तित्व यह देखकर निर्धारित किया जा सकता है कि क्या "बकाया पॉलिसियों के संबंध में देयता निर्धारित करने में नियोजित ब्याज दर या अन्य कारक प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के साथ भौतिक रूप से असंगत है।"

ऐसा हो सकता है कि गलत ब्याज दर या अन्य कारकों को नियोजित करके जिसके आधार पर बकाया पॉलिसियों के संबंध में देनदारी की गणना की जाती है, यह देनदारी सही राशि से काफी कम या काफी अधिक दिखाई जाती है। बकाया पॉलिसियों के संबंध में बीमा कंपनी की देनदारी की गणना एक तकनीकी मामला है और जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, ब्याज दर और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यह एक विशेषज्ञ के लिए मैट है और ये गणना आमतौर पर बीमा कंपनियों के कार्यरत बीमांकिकों द्वारा की जाती है।

बीमा नियंत्रक इन गणनाओं की सत्यता की जांच करने में सक्षम है और परंतुक का इरादा यह है कि जहां इस तरह के एक कठिन और जटिल मामले का संबंध है, आयकर अधिकारी को ऐसा करने से पहले बीमा नियंत्रक की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी परिवर्तन उसके अपने ज्ञान के आधार पर होता है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कोई कठिन मामला नहीं है और नियम 3(बी) और उसके परंतुक में उल्लिखित मूल्यांकन स्पष्ट रूप से सही मूल्यांकन है, क्योंकि क़ानून वास्तव में यह नहीं मानता है कि किसी गलत या धोखाधड़ी वाले मूल्यांकन को बिना सलाह के सही नहीं किया जा सकता है। बीमा नियंत्रक.

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एक आम आदमी द्वारा भी बाजार भाव के आधार पर किया जा सकता है। आयकर अधिकारी को इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है और मेरे विचार में, प्रावधान का उद्देश्य उन मामलों को कवर करना नहीं है, जहां एक निर्धारिती, आयकर से बचने के लिए, स्थानांतरित करते समय अपनी प्रतिभूतियों का अधिक मूल्यांकन करता है। उन्हें आरक्षित निधि में ले जाना या आरक्षित निधि की मात्रा में मूल्यह्रास दिखाने के लिए उन प्रतिभूतियों का कम मूल्यांकन करना जो पहले से ही आरक्षित निधि में हैं। हमारे समक्ष मामले में आयकर अधिकारी द्वारा किया गया समायोजन प्रावधान में अपेक्षित समायोजन के अनुरूप नहीं था। आयकर अधिकारी ने जो कुछ किया वह नियम 3(बी) द्वारा अनुमत आंकड़े पर अनुमेय कटौती की राशि तय करना था।

कटौती की मात्रा की गणना में उन्होंने प्रतिभूतियों के सही मूल्यांकन को आधार बनाया। आयकर कार्यालय का यह मानना बिल्कुल उचित था कि एक निश्चित संपत्ति का मूल्यांकन कम किया गया था। इस परिसंपत्ति का सही मूल्य तय करने में वह उस प्रकार का समायोजन नहीं कर रहा था जिस पर नियम 3(बी) के परंतुक द्वारा विचार किया गया है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 3(बी) मानता है कि प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों का सही मूल्य निर्धारण किया गया है। यह केवल सही मूल्य वाली संपत्तियों और बकाया पॉलिसियों के संबंध में देनदारी के बीच असमानता है जिसके लिए बीमा नियंत्रक के साथ पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है।

हमारे सामने जो मामला है उसमें स्पष्टतः ऐसा नहीं है। श्री हार्डी, जो आयकर विभाग की ओर से उपस्थित हुए, ने ब्यूमोंट, सीजे द्वारा इन री वेस्टर्न इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (1938) 6 आईटीआर 44: (एआईआर 1938 बॉम 345) में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया। . इस मामले में 1930 और 1931 के वर्षों में आरक्षित निधि में प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में कमी आई थी। इस मूल्यह्रास को कवर करने के लिए, कंपनी ने धनराशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया और दावा किया कि इस प्रकार हस्तांतरित राशियाँ अनुमेय कटौती थीं। ऐसा हुआ कि वर्ष 1932 में प्रतिभूतियों में काफी सराहना हुई और इस सराहना ने पिछले

दो वर्षों के घाटे को मिटा दिया, जिसका शुद्ध परिणाम कुल मिलाकर तीन वर्षों में एक छोटी सी वृद्धि थी।

आयकर अधिकारी ने वर्ष 1930 और 1931 के संबंध में की जा रही कटौतियों पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि वर्ष 1932 में बाद की सराहना को देखते हुए ये कटौतियाँ आवश्यक नहीं थीं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि 1932 की सराहना हो सकती है। निर्धारिती को उन वर्षों के संबंध में कटौती का दावा करने से वंचित न करें जिनके दौरान आरक्षित निधि में प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के कारण हानि हुई थी। ब्यूमोंट, सी.जे., ने टिप्पणी की-

"त्रैवार्षिक अवधि के पहले दो वर्षों में इन राशियों को उचित रूप से विशेष आरक्षित निधि में रखा गया है, मुझे उन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके लिए यह आवश्यक हो कि उन्हें मूल्यह्रास के तुरंत बाद राजस्व खाते में वापस लाया जाए जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया था मुलाकात अच्छी हो गई है।"

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा-

"लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष आरक्षित निधि में रखी गई रकम मूल्यह्रास या हानि के संबंध में होनी चाहिए, जिसका अर्थ है, मेरे विचार में, मूल्यह्रास या हानि, जो वास्तव में हुई है, और उस आरक्षित निधि का उपयोग किसी अन्य के लिए नहीं किया जा सकता है उद्देश्य।"

उस मामले में बीमा नियंत्रक से परामर्श नहीं किया गया प्रतीत होता है, स्पष्ट रूप से क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं था जो नियम 3 (बी) के प्रावधान के दायरे में आ सकता है। तब लागू नियम नियम 30 था। हालाँकि, इस मामले से जो बात उभर कर सामने आती है, वह यह है कि आरक्षित निधि में स्थानांतरण, हालांकि, यह है कि आरक्षित निधि में स्थानांतरण वास्तविक मूल्यह्रास या हानि और निर्धारिती के संबंध में होना चाहिए। जिन प्रतिभूतियों को वह स्थानांतरित कर रहा है उन्हें अधिक अनुमानित करके या आरक्षित निधि में पहले से ही मौजूद प्रतिभूतियों को कम करके कोई काल्पनिक या काल्पनिक आंकड़ा नहीं ले सकता है। श्री हार्डी द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य मामला, कॉमरेड का है। आयकर बनाम इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , (1946) 14 आईटीआर 347: (एआईआर 1946 सिंध 25)। यह भी एक ऐसा मामला था जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास का आरोप लगाया गया था। ब्यूमोंट, सीजे द्वारा पुष्टि किए गए सिद्धांत को इस मामले में दोहराया गया था, और सिंध मुख्य न्यायालय के डेविस, सीजे ने कहा-

"***नियम 30 के प्रयोजन के लिए आरक्षित निधि में जो उचित रूप से ले जाया जाना चाहिए वह कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे निदेशक अपने विवेक से कंपनी की भविष्य की स्थिति की

सुरक्षा के लिए, या भविष्य की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझते हैं, बल्कि केवल ऐसी राशि है मूल्यह्रास या हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ जो वास्तव में घटित हुई हैं या वास्तव में झेली गई हैं। *** * इसलिए, प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास से वास्तव में खोई गई राशि से बड़ी राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए निर्धारिती कंपनी खुली नहीं है। यह है यह सच है कि नए नियम 2, उप-नियम (3) के तहत, बीमा अधीक्षक के परामर्श के बाद आयकर अधिकारी को कुछ हद तक राशि को नियंत्रित करने का विवेक दिया गया है जिसे आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्रावधान माना जा सकता है और यह मुफ़्त होना चाहिए आयकर बनाते हैं, लेकिन यह, मेरी राय में, हमारे सामने मौजूद प्रश्न के उत्तर को प्रभावित नहीं करता है।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रावधान ऐसे मामले पर लागू नहीं होता है जहां आयकर अधिकारी को यह देखना होता है कि प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। उसे बीमा नियंत्रक के किसी भी संदर्भ के बिना खुद को संतुष्ट करना होगा कि जिन प्रतिभूतियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जा रहा है, वे मूल्यह्रास या हानि को पूरा करने के लिए अनावश्यक (एसआईसी) से अधिक नहीं हैं जो वास्तव में हुई हैं या वास्तव में भुगतना पड़ा है, और यह निर्धारित करने के लिए उसके पास प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन होना चाहिए। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कॉमरेड। आयकर का (1951) 20 आईटीआर 189: (एआईआर 1952 बॉम 637), एक और मामला था जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया गया था।

उस मामले में प्रशंसा न तो राजस्व खाते में दिखाई गई और न ही अधिशेष में; हालाँकि, इसे कंपनी की बैलेंस-शीट में दिखाया गया था। न्यायालय ने माना कि सराहना को अधिशेष में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसे आर. 3(बी) के अनुसार खातों में दिखाया गया था। श्री चावला, जो निर्धारिती की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि यह मामला इस प्रस्ताव का अधिकार है कि निर्धारिती के खातों में दिए गए आंकड़े बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किए जाने चाहिए। हालाँकि, फैसले में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का प्रश्न न्यायालय के समक्ष नहीं था।

प्रशंसा की राशि की गणना सही ढंग से की गई थी और न्यायालय का मानना था कि इस तरह की सराहना को अधिशेष में जोड़ा जाना चाहिए। यदि आयकर अधिकारी नियंत्रक से परामर्श किए बिना अधिशेष खाते में मूल्यवृद्धि जोड़ने का हकदार है, तो वह इस मूल्यवृद्धि की मात्रा भी निर्धारित कर सकता है। इस मामले में स्पष्ट रूप से बीमा नियंत्रक से परामर्श नहीं किया गया, क्योंकि निर्णय में आर. 3(बी) के प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है। ऐसा कोई निर्णय जिसमें नियंत्रक के परामर्श के प्रश्न पर विचार किया गया था, हमारे सामने उद्धृत नहीं किया गया था और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नियंत्रक से केवल उन मामलों में परामर्श किया जाना

चाहिए जहां प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को सही मानते हुए आयकर अधिकारी को असंगतता मिलती है आरक्षित निधि की राशि और बकाया पॉलिसियों के संबंध में देयता की राशि के बीच।

यह असमानता इस तथ्य के कारण हो सकती है कि ब्याज दर और देनदारी की गणना में नियोजित अन्य कारक गलत थे; यह प्रतिभूतियों के गलत या धोखाधड़ी वाले मूल्यांकन के कारण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि बाद के मामले में मूल्यांकन को नियंत्रक के किसी भी संदर्भ के बिना सही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में क्या हुआ कि निर्धारिती ने उपलब्ध अधिशेष से कुछ धनराशि निकाल ली और इसे आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने यह दिखाने के लिए हस्तांतरित राशि का कम मूल्यांकन किया कि आरक्षित निधि की मात्रा पूरी तरह से बकाया पॉलिसियों के संबंध में देयता के अनुरूप थी।

ऐसा कोई आरोप नहीं है कि देनदारी की गणना गलत तरीके से की गई है और आयकर अधिकारी ने इस मद में बदलाव करने की मांग नहीं की है और न ही करदाता का मामला है कि देनदारी अधिक होनी चाहिए। विवाद का मामला केवल आरक्षित निधि की मात्रा से संबंधित है और विवाद इसके मूल्यांकन तक ही सीमित है। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि यदि प्रतिभूतियों का मूल्य आयकर कार्यालय द्वारा बताए गए आंकड़ों पर किया जाना है, तो रुपये की राशि। स्वीकार्य कटौतियों में से 1,89,185/- की कटौती की जानी चाहिए।

इसलिए, मुझे लगता है कि आयकर अधिकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को सही करने से पहले बीमा नियंत्रक से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं था और उसके पास अपने द्वारा नियोजित तरीके से मामले से निपटने का पूरा अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, हमसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।

परिणामस्वरूप, याचिका (आयकर मामला संख्या 8-डी 1957) खारिज कर दी जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है। निर्धारिती इन कार्यवाहियों की लागत का भुगतान करेगा जिसका हम मूल्यांकन करते हैं। 200/-.

ए. एन. ग्रोवर, जे.- मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Deepak yadav

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh